nwda.gov.in

शहरों में विकास के साथ पर्यावरण की चुनौती

मनीष तिवारी ● जागरण

- समस्याओं से जूझते शहरों के लिए नहीं मिले किसी नए कार्यक्रम के संकेत
- मौजूदा योजनाओं के साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर जोर रहने के आसार

नई दिल्ली : अव्यवस्थित विकास के ठिकाने माने जाने वाले शहरों की दशा सुधारने का रोडमैप क्या है, इसका जवाब एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में मिल सकता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं जैसी अपनी मौजूदा योजनाओं पर ही आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही सरकार का जोर विकास और पर्यावरण संकट की चुनौतियों के बीच संतुलन कायम करने पर है।

अमृत मिशन में 500 शहरों में 5070 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास, 23 शहरों में मेट्रो का दायरा एक हजार किलोमीटर से ऊपर पहुंचना, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्टों पर जोर तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहरों की परिकल्पना सरकार के सोच की दिशा बताती है। छोटे और मध्यम श्रेणी के 169 शहरों में दस हजार पीएम ई बसों का संचालन भी इसी की एक कड़ी है। शहरी मामलों के विशेषज्ञ और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हितेश वैद्य के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण ने 2047 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत का खर्च 250 अरब डालर (21.64 लाख करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगा। शहरों को आज से ही इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। वित्त मंत्रालय का दस्तावेज भी बताता है कि शहरों के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है ताकि रोजगार उत्पन्न हो और लोगों को सुगम जीवन की सुविधा मिले, लेकिन प्रदूषण व जाम जैसी समस्याएं भी उतनी ही गंभीर हैं।

> मेट्रो का विस्तार और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम देश को विकसित बनाने की दिशा में सहायक साबित होंगे। अमृत योजना के तहत वाटर कनेक्शन का कवरेज 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
>
> **-मनोहर लाल**, आवासन और शहरी कार्य मंत्री

जल्द ही 29 हो जाएगी देश में मेट्रो वाले शहरों की संख्या

किफायती आवास (पीएम आवास योजना) और मेट्रो रेल सिस्टम पर सरकार बहुत अधिक खर्च कर रही है। सर्वे के अनुसार 900 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। जल्द ही मेट्रो वाले शहरों की संख्या 29 हो जाएगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ब्राजील और चीन जैसे देशों में 50 प्रतिशत से अधिक शहरी आबादी व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करती है, लेकिन भारत में 37 प्रतिशत लोग सार्वजनिक परिवहन और वह भी अव्यवस्थित के भरोसे है।